

श्री उपसभापति : बहस एक बार पहले हो चुकी है। (व्यवधान) आप ने नोटिस दिया है, आप को इत्तिला कर देंगे विचार कर के।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इस सवाल पर बहस से सरकार क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

श्री उपसभापति : बहस होगी तब पता चलेगा वह क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। आप ने नोटिस दिया है...

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : प्रक्रिया के अन्दर जितने नियम हैं उन सब नियमों के तहत हमने नोटिस दिये हैं।... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : बेरोजगारों के सवाल पर क्यों विचार नहीं किया जाता ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not record Mr. Rameshwar Singh. (Interruptions)

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

**REFERENCE TO THE
ALLEGED PRESS STATEMENT BY A
JUDGE OF CALCUTTA HIGH
COURT AGAINST WEST BENGAL
GOVERNMENT**

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, a Judge of the Calcutta High Court issued a Press statement calling the West Bengal Government a hypocrite. (Interruptions) I want to know whether a High Court Judge can indulge in politics like this. Will the Law Minister make a statement on this and... (Interruptions)

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, this cannot be raised like this. You should have taken permission for that. (Interruptions)

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please don't record him. (Interruptions)

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Sir, I have to bring a serious matter to the notice of the...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If it was a serious matter you should have taken my permission earlier. From this it appears that it is not a serious matter. You Should have written to me. (Interruptions) You give notice. I will consider it. (Interruptions) Whatever you want, you give notice in proper form. (Interruptions) Mr. Mathur, please. (Interruptions)

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't record Mr. Rameshwar Singh. (Interruptions) Mr. Mathur. Calling Attention, (Interruptions)

**CALLING ATTENTION TO A MAT-
TER OF URGENT PUBLIC IMPOR-
TANCE**

Reported increasing cases of forgeries in Banks and recent unearthing at different places of a racket involving transference of black money amounting to several crores of rupees through Bank demand drafts

श्री जगदीश प्रसाद मावुर (उत्तर प्रदेश) : श्री मान, बैंकों में जालसाजी के बढ़ते हुए मामलों तथा विभिन्न स्थानों पर बैंक डिमांड ड्राफ्टों के जरिये कई करोड़ रुपए के काले धन के अन्तरण संबंधों घोटाले का हाल में पता लगाये जाने के समाचार और इस संबंध में सरकार द्वारा की गयीं कार्यवाही को और भी वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI IANARDHANA POOLY); Sir, information was received that some shroffs at Bombay under the cover of discounting bank drafts were indulging in helping transfer of unaccounted sale proceeds of goods. In pursuance of this information, the searches were conducted on 25th July, 1983 covering 19 premises at Bombay. The premises of some banks were also covered. The searches resulted in seizure of cash/bank drafts of Rs. 32.05 lakhs and bank accounts with balances of Rs. 18.49 lakhs were frozen. It is believed that about 100 to 150 shroffs are doing this business in Bombay and their daily turn over ranges between Rs. 50,000 to Rs. 5 lakhs. Taking an average figure of Rs. 1 lakh per shroff the total drafts discounted would amount to Rs. 10 crores per week approximately.

Similar searches had been conducted by the Department earlier on 7.5.79, 13.9.82 and 21.3.83 also in which cash/drafts of Rs. 19.04 lakhs, Rs. 37.02 lakhs and Rs. 21.4 lakhs respectively were seized.

In the first search, the drafts were seized only after they had been cleared but in subsequent searches the Department had seized them before they could be sent for clearing. A number of shroffs had already offered to be assessed on the amounts of drafts including estimated commission earned on entire business. The Department is collecting the original draft applications, the account opening forms and other evidence for completing the assessments in these cases.

As regards cases of forgery in banks, some cases have come to notice. The Finance Minister had taken a meeting of the Chief Executives of the Public Sector Banks on the 14th April, 1983. At the meeting, the banking developments with particular reference to the need for improving the image of the banking system and appropriately dealing with the complaints about poor service, prevalence of corruption/malpractices in banks and increasing incidence of frauds were considered at length. Banks were specifically advised to review and revamp the

vigilance machinery, take urgent steps to tone up control and supervision, strengthen management information system, follow-up and inspection/audit arrangements and draw up a time-bound programme for clearing the arrears and balancing of books and reconciliation of inter-branch and other accounts. The Reserve Bank also have issued detailed instructions inviting the attention of the banks to areas and problems which require their immediate attention.

The Reserve Bank of India has set up a special cell to look into serious complaints and cases of corruption of fraud which have inter-State or wider ramifications. The banks have also strengthened their vigilance machinery and have arrangements for deputing officers on the spot for paying special attention to cases of corruption and other complaints.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वक्तव्य एक विसा-पिटा-सा वक्तव्य है जो लोक सभा में दिया जा चुका है। यह वही है। इस में कहा गया है कि हम केसेज हैव कम टु नोटिस। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान सिंडिकेट बैंक की ओर दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने पढ़ा भी होगा—सन्डे नाम का अखबार है उसमें यह सारा घोटाला छपा है और स्वयं इस वक्तव्य में स्वीकार किया गया है कि बैंकिंग सिस्टम पर से लोगों का विश्वास घट गया है और प्रयत्न किया जाएगा कि किसी प्रकार से बैंकों के कार्य में लोगों की आस्था फिर से स्थापित हो। आस्था क्यों डिंग रही है इस का एक उदाहरण भी आप ने दिया है। लेकिन सब से बड़ा उदाहरण सिंडिकेट बैंक का है जिस के डिपेंडेंस में मैं नहीं जाऊंगा। वहां के चेयरमैन के खिलाफ साबो आई ने कार्यवाही की है और वह कार्यवाही अभी पूरी हुई भी नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि सिंडिकेट बैंक जिस के चेयरमैन के और अधिकारियों के खिलाफ साबो आई

की कार्यवाही हुई है, जिस के डिटेल यहां दिखे हुए हैं, करोड़ों का मामला है तो क्या सरकार इस नीति को नहीं अपनायेगी कि बड़े अफसर और छोटे क्लर्क समान होंगे और उन सब पर कार्यवाही की जायेगी। मैं मांग करता हूँ और माननीय मंत्री से चाहूंगा कि सिडिकेट बैंक के जो मिस्टर रघुपति हैं उन को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? उन को हटाया क्यों नहीं गया जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती? इतनी बात मैं इस विषय में जरूर कहना चाहूंगा कि उन को हटाया जाना चाहिए और सिडिकेट बैंक की सारी कार्यवाही उन को मालूम होगी।

जो घोटाले हो रहे हैं वह बैंकों में प्रायः तीन प्रकार के हैं। पहले कि वे जो बैंक के कर्मचारियों की सहायता के बिना बाहर के आदमी करते हैं। दूसरे वे हैं जिन में कोई बाहर का आदमी होता है और कोई बैंक का कर्मचारी होता है और तीसरे वे हैं कि जिन को केवल बैंक के कर्मचारी ही करते हैं। पहले, बंबई के संबंध में जहां तक काले धन को वापस लेने की कार्यवाही हो रही है, उसमें आप ने कार्यवाही की है। मैं उस का स्वागत करता हूँ। लेकिन उसमें एक बात रह गयी है। आपने आर्डर नहीं किये हैं, केवल घोषणा की है कि जो ड्राफ्ट बनेगा 5000 का या उससे ऊपर की रकम का उस में उस का एड्रेस आदि देना पड़ेगा अभी तक आप ने इस के लिए घोषणा की है लोकसभा में, लेकिन बैंकों के पास इंस्ट्रक्शन्स नहीं गये हैं इस को शोध किया जाना चाहिए। लेकिन इस के साथ ही जो ऊपर की रकम के ड्राफ्ट हैं, 10 हजार के ऊपर के उन के लिए आप ने निश्चय किया है जो कुछ मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट करें

कि उस के अंदर कोई न कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला आदमी होना चाहिए जैसे किसी को बैंक एकाउन्ट खोलना होता है उस तरह से होना चाहिए। तो अगर यह इंस्ट्रक्शन हो जायेंगे तो ठीक होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कब तक हो जायेगा और यह कब से लागू होगा? लेकिन यदि कोई बैंक में जा कर 9999 का ड्राफ्ट बनवा ले और ऐसे ही दस ड्राफ्ट बना ले तो क्या यह बात उस पर लागू होगी या नहीं। तो मेरा आग्रह है कि इस पर आप ध्यान दें। अगर कोई एक ही बैंक को डिफरेंट ब्रांचेस से 9999 रुपए के दस ड्राफ्ट बनवा लेता है और वह टोटल मिल कर 10 हजार से ज्यादा हो जाता है तो उस पर भी यह रिस्ट्रिक्शन लागू होना चाहिए। यह काले धन का घंघा है। इस को रोकना सरल नहीं है। इसलिए मैं इस बात को और ज्यादा लम्बा नहीं करता।

दूसरे तरह के घोटालों में बैंक के कर्मचारी मिले रहते हैं। इस में प्रायः दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो यह कि मेरी कंपनी है और उस का बैंक में एकाउन्ट है। उन को मालूम होता है कि हमारा बैलेंस लाख से कम नहीं होता तो बैंक कर्मचारी क्या करते हैं एक दूसरी जिस कंपनी वाले से उन को दोस्ती है उस से मिल जाते हैं और यहां जो रुपया जाता है मेरा वह दूसरे के एकाउन्ट में जैसे 50 हजार रुपया गया तो उसे दूसरे एकाउन्ट में चढ़ा देते हैं और उससे दूसरी कंपनी को एडवांस कर देते हैं और दस दिन बाद वह पैसा फिर वापस आ जाता है। और रिवर्स इंट्री कर दी जाती है। वह पैसा हफ्ते दस दिन उपयोग कर लिया जाता है। अगर पता लग जाता है तो कह देते हैं कि गलती हो गयी और उस को रिवर्स इंट्री बॉच में कर हो दी जाती है

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर] इस चीज को आपको करना होगा।

दूसरे, इसमें जो गड़बड़ी ही रही है जिसकी आपको रोकना होगा वह यह है कि दिल्ली में हजारों केसेज ऐसे हैं जहाँ पर कि क्लियररेंस क्रेडिट बैंक पास कर दिये जाते हैं। जैसे आज शुक्रवार है, क्लियररेंस के लिए बैंक भेजा गया, कल सेटरडे है, फिर सन्डे हो गया, छुट्टी हो गई और पैसे उसको दे दिया, चार दिन तक वह पैसा अपने पास रख लिया। सन्डे या ट्यूजडे को जब बैंक वापस आया तो कह दिया कि गलती हो गई तो मेरा आग्रह यह है कि क्या आप यह इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब तक पूरा क्लियररेंस नहीं होता तब तक कोई क्रेडिट का पेमेंट नहीं होगा, इस घपले को रोकने के लिए ?

दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूँ वह घपला जो बैंक के कर्मचारी करते हैं। दिल्ली में कई बैंक ऐसे हैं जहाँ ब्रांच मैनेजर घपला करते हैं। फिक्टोशस नाम से, लल्लू, कल्लू, मोटल्लू, मजाद हमीद नामों से, उनको लोन देते हैं रिक्शे का लोन या जो भी लोन मिलता है, वह दे देते हैं। वह प्रावमो ऐक्जिस्ट नहीं करते और जब सल या 6 महीने में कोई पकड़ में नहीं आता तो कह देते हैं कि राइट आफ कर दिया जाए। इस तरह से वह पैसा राइट आफ हो जाता है। इसको रोकने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बतायें।

एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे साथी नाराज न हों इसलिए मैं नाम नहीं लेता। यहाँ पर एक बैंक आफ इंडिया को राणा प्रताप बाग में ब्रांच है, उसमें नोटिस लगाया गया, उसमें लिखा गया कि ये ये लोन मिलेंगे वशतें कि अनुरूप अनुरूप लोकल एम० पी०, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, को सिफारिश

लेकर उस दिन तक अप्लीकेशन आ जाए। यह दूसरे प्रकार का फ्राड है कि बैंक के मैनेजर नोटिस लगाते हैं कि लोकसभा दिल्ली के जो मेम्बर हैं उनकी सिफारिश होगी तो इस तारीख तक लोन दे दिया जाएगा। यह दूसरे प्रकार का भ्रष्टाचार है, इस चीज को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

मैं कुछ मोटे-मोटे प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री सतपाल मिश्रल : क्या (पंजाब) एम० एल० ए० की सिफारिश से नहीं होता है ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसी वास्ते मैं नाम नहीं लिया कि आप नाराज होंगे। वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है कि यदि फलों फलों एम० पी० की सिफारिश होगी तो लोन दिया जाएगा। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बैंक वालों की कर रहा . . . (व्यवधान)

कुमारो सरोज खापड़ (महाराष्ट्र) : कहीं आपने झूठा नोटिस तो नहीं लगाया बैंक के सामने . . . (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं आपसे वहस करने का आदी नहीं हूँ भायद. यह कला आप लोग सिखा सकते हैं, अपने बस का रोग नहीं है . . . (व्यवधान)
मैं आपकी ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार हूँ, बोलिए कब हाजिर होऊँ ?

श्री सतपाल मिश्रल : आपकी कांस्टीट्यूयेंसी का मैनेजर है उसने आपका नाम नहीं लिया, दूसरे से क्या सिफारिश करवाते हैं, इसलिए आप कहते हैं (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं आपका नहीं बित्त मंत्री जी का ध्यान इधर दिता रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। सिफारिश

हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए नोटिस लगता है, उससे आपको वह बदनाम करते हैं . . . (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापडें : अगर यह खबर आपके घर आई है तो आपका फर्ज बनता है कि उस नोटिस को फाड़कर अपने पास रखना चाहिए था और सदन के सामने लाना था इस तरह का नाम लेकर आप अल्टीमेटली किसको बदनाम करना चाहते हैं।

DR. RAFIQ ZAKARIA (Maharashtra): Sir, I am on a point of order.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं तो बैंक का नाम बता रहा हूँ . . . (व्यवधान)

DR. RAFIQ ZAKARIA Mr. Deputy Chairman, Sir, my point of order is that according to the Rules of Business, . . . (Interruptions):

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : कालिंग अटेंशन पर प्वाइंट आफ आर्डर एलाऊ करते हैं तो हम भी त्वाइंट आफ आर्डर उठायेंगे।

श्री उपसभापति : आप तो बिना नियम के उठाते हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : कालिंग अटेंशन में ऐसा नहीं होता है। आप परम्परा को विगाड़ रहे हैं।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, my point of order is that this is a matter which we have been seeing since 12 o'clock. The way the things are going on in today's meeting of the Business Advisory Committee we will have to take a serious view of the whole thing. I do not think that anybody can conduct a certain business with certain Members shouting at the top of their voice and trying to create a situation wherein it is doubtful whether this will remain really the Rajya Sabha. We have to seriously consider this matter. Sir, my point of order is that Mr. Mathur has made a reference to a particular document, a notice having been put up. I want to

know whether according to the Rules it should not have been shown to the Presiding Officer. It is only after it had been shown to the Presiding Officer and the Presiding Officer was satisfied that he could refer to it. Now, Sir, it has been said from the other side how can it be done. I cannot understand that any manager in his sense would put up such a notice.

AN HON. MEMBER: Let him take the responsibility of what he is saying.

DR. RAFIQ ZAKARIA: Yes, Sir, let him take the responsibility of what he is saying. Not only that, Sir. In such cases you will have to make the Member, who makes such kind of allegations, suffer some kind of consequence, also. (Interruptions).

श्री जे० के० जैन (मध्य प्रदेश) : हमेशा इस सदन में यह देखा गया है कि एक खास सदस्य इस तरह के झूठे और बेहूदा आरोप यहां लगाते हैं यह कह कर लगाते हैं कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। इस तरह के आरोप लगाकर यह दुनिया भर की झूठी बातें, अनर्गल बातें यहां रिकार्ड में ले आते हैं। इंटरनेशनल प्रेस यहां होता है। प्रेस में ये सारी बातें आ जाती हैं। झूठे आरोपों की यदि यह जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आइन्दा इनके इस तरह के अनर्गल शब्द रिकार्ड में नहीं जाने चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनको वार्निंग दीजिए कि ये झूठी बेबुनियाद बातें न करें। (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापडें : हमेशा आप इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और सरकार की गरिमा को गिराने की कोशिश करते हैं। आप जैसे सीनियर एम० पी० के लिए यह शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय सदस्य ने जो अनर्गल और बेहूदा

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

शब्द का इस्तेमाल किया है अगर ये पार्लियामेंट के रिकार्ड में लिखे जायेंगे तो दूसरे सदस्यों को भी ये शब्द कहने का मौका मिल जायेगा (व्यवधान)

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat): Sir, my point of order is regarding the procedure.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let that point of order be over.

SHRI MANUBHAI PATEL; I am on that itself (*Interruptions*). Sir, my very objection is to the Yery procedure you are allowing. Sir, it is Calling Attention and when he has already moved it., it is first the Minister who has to reply to it.

Thereafter, if the other hon. Members want to ask questions, they can ask according to their turns. They can do it. But now they are discussing it between themselves as if the Chair is absent. And Sir..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: At least you are seeing the Chair. (*Interruptions*)-

SHRI MANUBHAI PATEL: One point raised by Mr. Zafcaria is practically amounting to defame the Members on the opposite side for the wrong procedure undertaken and then, Sir, at the top of it.. (*Interruptions*). Let me finish. Then, Sir, at the top of it Mr. Iain in Hindi alleges and uses the words which are unparliamentary which you have... (*Interruptions*)

Sir, I ask whether the word "Jhootha"-----

श्री जे० के० जैन : बेहूदा मीने कहा है । बेहूदा शब्दों का इस्तेमाल मीने किया है । झूठा मीने... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard..

SHRI MANUBHAI PATEL: 'Jhootha' word is unparliamentary, #5j %7f(H ^T I sn<r fare zm sftfarx 1 You should control this, type of wild allegation .. (*Interruptions*).

श्री जे० के० जैन : उपसभापति महोदय, अगर झूठी बातें कही जाएंगी तो एक बार नहीं हजार बार कहेंगे । झूठी बातें नहीं कहेंगे... (व्यवधान)

SHRI MANUBHAI PATEL; What I want to say is, when the Member » speaking on his calling attention motion, can any other Member reply on behalf of the Minister? Secondly, while interrupting, M-Iain has used the word 'Jhootha' and when I drew your attention..

SHRI J. K. IAIN: What is the full sentence?

SHRI MANUBHAI PATEL; Please. please. I am on my legs.. (*Interruptions*). You cannot cow down everybody..

SHRI J. K. IAIN: You mean, you will go on saying anything you want?

SHRI MANUBHAI PATEL; You sit down, when I am on my legs. t

SHRI I. K.(TAIN: You sit down..- (*Interruptions*).

SHRI MANUBHAI PATEL; I am *>t afraid; you cannot take us... (*Interruptions*). Is it the way?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: May I request the hon. Members.. (*Interruptions*) .

SHRI MANUBHAI PATEL : Why should he* me like this? Is he the custodian of the House?

MR. DEPUTY CHAIRMAN; Please don't get agitated. " *

SHRI MANUBHAI PATEL: And o» top of it, he is* as if he is conducting the party. I am not under his obligations..

MR.^DEPUTY CHAIRMAN: Please don't lose your temper and don't get agitated on any matter. It is usual some of the Members speak on top of their TOice; some others can make very forceful arguments while speaking in low voice. It differs from person to person. What can I do.

*Expunged as ordered by the Chair.

Now, may I request the hon. Members to- resume their seats? A point of order has* been raised about Mr. Jain's observation*. I think, Mr. Patel, you will appreciate the difference. The sentence that Mr. Jain used, I do not think it is unparliamentary.

SHRI MANUBHAI PATEL: What was that sentence? Did you hear?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard it; you will see it.

SHRI MANUBHAI PATEL: If I say 'Jhoofhcf....'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You say* the record*. If he alleges some word against a person, then it becomes unparliamentary.

SHRI MANUBHAI PATEL: He has said it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said about certain statements as not being correct, as false. He has said it "about the statement. That would be there. But it is not against any person.

So far as* the point raised by Dr. Zakaria is concerned, I would like to impress upon Shri Mathur, please don't name the House also, and I think you take the full responsibility for whatever allegations you are making. And if they are wrong, you will have to face whatever may be the consequence.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमान्, मैंने सिर्फ यह कहा है... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You don't name the House also.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने यह कहा है कि उसकी एक फोटोस्टेट कापी सभ्यद्वारों में छपी है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं बिया है... (व्यवधान)।

कुमारी सरोज खापड़ें : माननीय सदस्य से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगी कि

जिस चीज की कापी सभ्यद्वारों में छपी है उस सभ्यद्वार की कापी क्या वे सदन में ला सकते हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जरूर लेकिन चूंकि कागज सदन की टेबल पर रखने का रिवाज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं रखा है... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : अब आप सवाल पूछिये।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Let him proceed now and put his questions.

कुमारी सरोज खापड़ें : मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि... (व्यवधान)।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप यहां क्यों रुक रही हैं। मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने यह पूछा है कि जो बातें सभ्यद्वारों में छपी हैं, क्या आप उसकी जांच करेंगे और यह देखेंगे कि इस प्रकार के नोटिस नहीं लगने चाहिए ? ... (व्यवधान)।

श्री जे० के० बंस : आपको शर्म आनी चाहिए... (व्यवधान)

श्री मनुभाई पटेल : फिर * कर रहे हैं... (व्यवधान)। * आदमी हैं... (व्यवधान)।

श्री सतपाल मिश्र : श्री मनुभाई, आप बहुत ही माननीय सदस्य हैं। यह नहीं हो सकता है। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया है...

SHRI SAT PAUL MITAL: I object to his expression, Sir.

♦Expunged as ordered by the Ouer

कहा है ?

SHRI MANUBHAI. PATEL: Please control him.

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइये, म देखूंगा ।

श्री सतपाल मित्तल : देखिये यह ठीक नहीं है ।

श्री मनुभाई पटेल : मित्तल साहब आपने उनकी बात सुनी नहीं । वे हमको कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए । अब बात तो खत्म हो गई है तो न्हाई गुड ही... (व्यवधान)... वान खत्म हो गई ।

Why should he say like that? Should I take it lying down?

श्री सतपाल मित्तल : आपने गलत बात कही है... (व्यवधान)...

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : एक मिनट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । श्रीमन्, सदन की यह परम्परा रही है कि ...

श्री उपसभापति : छोड़िये इसको ।

श्री रामेश्वर सिंह : कोई अगर किसी का नाम भी लेता है, बहुत से मुख्य मंत्रियों के यहाँ नाम लिये गये...

श्री उपसभापति : अब आप बैठ जाइये । आप दूसरा नाम मत लीजिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : यहाँ नाम पर आपत्ति नहीं होती । यह सदन जो है वह सही बात कहने के लिये है । इस सदन में हम आये हैं, सही बात कहने के लिये आये हैं । हो सकता है कि इससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे । लेकिन हमको सही बात कहने में संकोच नहीं करना चाहिए ।

श्री उपसभापति : ठीक है ।

श्री जगदीश प्रताप सायूर :: जितनी बैंकों को बैंकिंग है, उसकी रिजर्व बैंक जांच करता है । होता क्या है, जो बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, उनका तीन साल में एक बार होता है या मुख्य जो कार्यालय हैं उनका साल भर में एक बार होता है । लेकिन रिजर्व बैंक, जो छोटी शाखायें हैं, उनका कभी आडिट देख नहीं पाना जैसे मैंने घपला बताया, खोन दे दिया, वापस ले लिया, यह जो ये शाखायें हैं इनमें अधिक है । दूसरी तकनीक क्या होती है कि जो आडिट के लिये रिजर्व बैंक से लोग आते हैं, वे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होते हैं They are not wellversed in bank accounting. बैंक एकाउन्टेन्ट्स के बारे में उनकी जानकारी नहीं होता । उनको सरकार दो-तीन हजार रुपये देती है और वे जल्दी जल्दी क के भाग जाते हैं और इस तरह घपले पकड़ में नहीं आते । मेरा पूछना यह है कि यह जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स हैं, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अन्दर आडिटर्स को जानकारी दी जाये और वे विशेष रूप से इसकी शिक्षा ले ताकि जब वे बैंकिंग करे तो सारे घपले पकड़ में आ सकें ।

दूसरा जो पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स कमेटी है, उसके अधीन बैंक घोटालों की जांच नहीं है । क्योंकि बैंक भी नेशनलाइज्ड हैं, वे हमारी सरकार और सदन के अधीन हैं, इसलिये मेरा निवेदन यह होगा कि क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि बैंकों के जो घोटाले हैं, उनकी जांच भी पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स कमेटी के अधीन हो । तीसरा जो छोटे कर्मचारी गड़बड़ करते हैं, उस में एक और कारण भी है कि बैंक में, आपको और सदन के बहुत से मित्रों

को जानकारी होगी और बहुतों को नहीं भी होगी, जैसे और सरकारी कर्मचारियों की कॉन्फिडेंसियल रिपोर्ट लिखी जाती है, लेकिन बैंक कर्मचारियों की कॉन्फिडेंसियल रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। इसलिये जो बैंक मैनेजर हैं, वे कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि उनके हाथ में उनकी कोई नक्कल न हो। मेरा निवेदन यह है कि क्या वित्त मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि बैंक के अन्दर भी जो कॉन्फिडेंसियल रिपोर्ट है, वह लिखने की पद्धति अपनाई जाये। दूसरा जो बैंक के मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं उनको कम से कम इतना अधिकार होना चाहिए कि अगर किसी कर्मचारी की गड़बड़ी या बेईमानी हाथ में आती हो तो उसको स्पॉट किया जा सके। लेकिन महीनों, वर्ष लग जाते हैं और कोई काम नहीं होता।

मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी भी चाहूंगा कि रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उस रिपोर्ट में, मुझे यह जानकारी दीजियेगा कि ऐसे कितने मामले हैं, जिन मामलों में सीधे कर्मचारियों ने बेईमानी की है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? आज, मैं समझता हूँ कि आप सारी रिपोर्ट दे नहीं सकते ...

श्री उपसभापति : बहुत बड़ी हो जायेगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह बिल्कुल सच बात है, नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसको समय समय पर कम से कम एक वर्ष के अन्दर यह होना चाहिए कि कौन कौन से घपले कैसे-कैसे हुए हैं और उसकी सत्यता के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर एक पालिसी का निर्धारण किया जाना चाहिए।

SHRI JANARDHANA POOJARY; Sir, at the very outset, I appeal to all the senior Members of this House to

seriously discuss this issue in this House in fact, this has to be discussed in an atmosphere of cordness. Otherwise, we will not be in a position to have any effective discussion. Sir, we share the concern of the hon. Members regarding the increase in the cases of frauds in the banks and also the channeling of black money through bank drafts. Some of the employees are black sheep in the banking industry also who are involved in this type of fraud. We have identified the areas. The hon. Finance Minister has called the meeting of the chief executives. He has also discussed the matter with the Reserve Bank Governor. He has suggested the corrective measure, to the banking people. So, the Government is very keen to curb the activities which are not above Board and the Government is going to deal with the persons who are indulging in bank fraud, particularly in this instant case also.

Hon. Member has raised some of the questions and he has also suggested some of the measures. I am grateful to the hon. Member for having suggested some of the measures and, in fact, we have noted them and we will keep them in mind while taking action in the matter.

Apart from this, in order to curb the activities that he has stated, in the main reply itself we have said that we are going to set up some of the advisory Committees at block level. These block level advisory committee are going to be set up to find out the malpractices and also to suggest corrective measures. On 3rd August 1983, the Finance Minister has written to the Chief Ministers to set up advisory committees at block level and these committees will have three non-officials also. (Interruptions) I am just coming to that. Particularly, we want to have the cooperation from the public, from the people at large from the responsible persons in the society who can look into these corrupt practices, malpractices. So, we are not going to give a blanket reply that all is well in the banking sector. We admit that there are malpractices. We are not going to defend any employee. On the contrary I myself have paid surprise visits to 200 branches and also various

L. S. Janardhana Pojary LIC and General Insurance branches, and the hon. member is correct in saying that there is increase in the cases of frauds. When I went there, I personally came to know from the ledgers that some of the inter-branch reconciliation was pending since the year 1973. In some of the branches the current account balancing and also the savings bank balancing was pending since 1978 or 1979. In some of the branches this has been pending since 1980 and 1981. That is why we called the meeting of the chief executives. We have told them in clearer terms that they should pay surprise visits. The chief executives were not expected to go abroad, they were expected to pay surprise visits even to the banks which are inside our country. They have also to pay surprise visits to rural areas, branches in order to find out the deficiency in the banking system. So, all the measures have been taken and corrective measures have been suggested. We are not complacent and we fully share the concern of the hon. member. On the contrary, we require assistance. You have brought to the notice of the Government one instance. If you kindly give the details of any other cases, we would certainly look into them.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : भ्रमर भ्रम

हिन्दी जानते हैं तो

He has

said that the Government is pro-losing to have advisory committees at a lock level. If he can possibly tell us as to what is the authority because it may only politicise the thing but it may also add to corruption if the Advisory Committees do not work in a proper manner.

Secondly, he has not said anything about Mr. Raghupathi, the Chairman of the syndicate Bank who has been raided by the CBI and he is still not under suspension. What about him?

SHRI JANARDHANA POJARY : here also, investigation is being conducted by the CBI. Now something has been found out there in his premises. That has come in the papers and I do not want to go into details about it. The Government is very serious about it also and the completion of the investigation... as far as Sir, there is judiciary also in

u

this country. If we take any hasty step, there will be repercussions. Anyway, it is under active consideration of the Government as to what action has to be taken. We are not going to shield anybody. That assurance I can give to the hon Member,

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) :
उपसभापति महोदय, अभी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हम सदन में बहस कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना यह होगी कि मैंने एक बार वित्त मंत्री जी से प्रश्न किया था और वह कुछ निजी बैंकों की गड़बड़ी के बारे में जब मैंने प्रश्न किया तो उसका उत्तर आया कि यह बैंक प्रणाली के नियम में सन्निहित है कि इन बातों को लोकहित में प्रकाशित करना उचित नहीं है। जब बैंक में पूँजी जनता की है, हम बैंकों में अपनी पूँजी जमा कराते हैं और सरकार के नियमों के अनुसार बैंक में से वे लोगों को कर्जा या रोजगार के लिए पूँजी देते हैं तो जनता की पूँजी आप कम दर पर, सुद पर लेते हैं और अधिक सुद पर देते हैं फिर भी आप मुझको नहीं बताते हैं कि आप जो रुपया दे रहे हैं वह जायज दे रहे हैं, नाजायज दे रहे हैं? आप कहते हैं कि यह गोपनीय है।

मुझे एक लक्ष्मी कामाक्षियल बैंक का ख्याल है उसके बारे में रिजर्व बैंक के द्वारा बताया गया कि रिजर्व बैंक ने अपनी जांच के दौरान कुछ त्रुटियां पायीं और उनको इस सम्बन्ध में सुधार के लिए कहा गया। लेकिन जब मैंने फिर प्रश्न किया कि रिजर्व बैंक ने जांच में क्या-क्या त्रुटियां पायीं थीं और अब तक क्या सुधार हुआ तो कहा गया कि लोकहित में उन त्रुटियों को बताना ठीक नहीं है। अब यह लोकहित हिन्दुस्तान में क्या चलाया है कि यह लोकहित तो लोकहित को ही काट रहा है। लोकहित के नाम पर लोकहित का बलिदान हो रहा है। अब व्यापारी के बारे में प्रश्न पूछा कि

अमुक-अमुक व्यापारियों को बैंक से कितना-कितना कर्जा दिया गया और कितना-कितना बैंकों से लिया तथा किस काम के लिए लिया और उसने जिस काम के लिए लिया था क्या उसने उस काम में वह पैसा इस्तेमाल किया या नहीं? तो जवाब आया कि बैंक की गोपनीय प्रणाली के मुताबिक इन बातों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप बैंकों के घोटाले गोलमाल को देखना चाहते हो तो ये, नियम ही आपके इन घोटालों और गोलमाल पर पर्दा डालते हैं। हमारे बिहार में भी मोतिहारी जिले का सवाल आया, अखबार में भी प्रकाशित हुआ कि हमें कि कई एक हजार पम्प सेट हरिजनों को देने के नाम पर बैंक वालों ने रूपा दे दिया, हरिजनों के नाम पर बांट दिया और जब इसकी इन्वॉयरी की गयी तो एक भी पम्पिंग सेट किसी हरिजन के घर पर नहीं पाया गया। पूरी इंडिया पम्पिंग सेट कम्पनी ही फोज्दौरी, जिन आदमियों को दिये गये, वे भी जाली थे, दस्तखत करने वाले जाली थे, लेने वाले जाली थे, देने वाले जाली थे और बैंक से निकल गया कई लाख रुपया और आज तक एक भी आदमी उसमें गिरफ्तार नहीं हो पाया। यह मेरे बिहार का मामला है। यह भी मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।

सरकार ने बम्बई में एक सौ डेढ़ सौ सर्राफ के बारे में अनुमान किया है। ये अनुमान करते हैं कि बम्बई में एक या डेढ़ सौ सर्राफ घंघा करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि जो एक या डेढ़ सौ आदमी इस धंधे में लगे हुए हैं उनमें से कुछ के घरों पर आपने छापामारी कराई है? केवल संख्या बता दीजिए

कि इन सौ डेढ़ सौ सर्राफों में से कितनों के घर पर छापामारी की गयी। कितनों के, बैंकों में जो एकाउंट्स हैं उनकी तलाशी ली गयी और फिर उनके घर से कागज पत्र बरामद हुए। यह कितनों का किया गया। क्या यह सही नहीं है कि उनमें कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनके घरों पर छापामारी नहीं की जाती है? छोटे-छोटे घरों पर छापामारी की जाती है ताकि बड़ी मुर्गी स्वयं डर से झंझा दे दे और वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सरकार की टोकरी में जमा हो जाये। तो क्या यह भी इस में हुआ है या नहीं? यह भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, पूरा-पूरा बताइये। आप ने कहा कि 14 अप्रैल, 1983 को एक बैठक आप ने बुलाई थी बैंक के बड़े-बड़े अधिकारियों की। उस बैठक में जो तय किया था उसके मुताबिक क्या-क्या अब तक नीति निर्धारित किया और कौन-कौन सी कार्यवाही करने का आप ने फैसला लिया है? जो कुछ भी आपने फैसला लिया है कृपा कर के बतायें। केवल मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। आप ने इस सम्बन्ध में क्या निर्देश जारी किये हैं वह भी मुझ को बताने की कृपा करिये। सब से आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने यह प्रश्न किया था कि बिहार में किसानों को जो कर्जा दिया जाता है वॉरिंग पम्पसेट के लिए ओपिन मार्केट में पाइप 18 रुपये के भाव और बैंक भुगतान कर रही है 26 रुपये के भाव से, ओपिन मार्केट में पम्पसेट 4 हजार का और बैंक भुगतान कर रहा है 5500 के भाव से। जब मैंने यह प्रश्न पूछा तो उत्तर दिया गया कि रिजर्व बैंक को इस की जानकारी नहीं है कि इन चीजों की खुले बाजार में क्या कीमत है। मुझको इस शताब्दी की सब से झूठी बात यही समझ में आयी। रिजर्व बैंक की बुलेटिन से होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

लोग पढ़ा करते हैं। तो रिजर्व बैंक जो बुलेटिन होलसेल प्राइस की, रिटेल प्राइस की निकालती है उसे इन चीजों की बाजार में क्या कीमत है पता नहीं होगी तो इस का मतलब है कि रिजर्व बैंक जो प्राइस छापता है वह सब झूठी है क्योंकि कि उन को पता नहीं है। वह झूठी नहीं होगी तो जो उत्तर दिया गया वह झूठ है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि इस की मुस्तैदी से जांच कराई जाय। क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी, जांच समिति बनायेगी या संसदीय समिति बनायेगी, लेखा-जोखा की जांच करने के लिए कोई संसदीय समिति बनायेगी जो इस बात की जांच करे कि बड़े-बड़े घराने उद्योगपति जो रुपये उद्योग को खड़ा करने के लिए लेते हैं उन रुपयों को दूसरे काम में खर्च नहीं करते? क्या यह जालसाजी नहीं है? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जालसाजी नहीं होगी। अगर आप और जांच नहीं कराएँ तब भी संसद भवन के सामने, विडसर प्लेन पर जनपथ के सामने प्योर ड्रिक्स के पांच-सितारा होटल के लिए रुपया कर्ज लिया गया 10 करोड़ 50 लाख। सारा सीमेंट, लोहा, आप ने दिया है। इस की जांच होनी चाहिए कि वह प्योर ड्रिक्स वाले 10 करोड़ 50 लाख रुपया होटल को बनाने में लगाये हैं या उस से निजी सम्पत्ति अर्जित की है, मकान बनवाया है। उसी से एणो-आर.म. होगा, उसी से लिपिस्टक-पावडर लेंगे, सब उसी रुपये में से होगा।

श्री उपसभापति : आप कहां से कहां चले गये, अब आप समाप्त करिये।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : समाप्त कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यह सब से बड़ी जालसाजी है।

श्री उपसभापति : आप लोन की बात कर रहे हैं, यह लोन का सवाल नहीं है।

श्री हुक्म देव नारायण यादव : जालसाजी क्या है? मैंने बैंक से रुपया लिया कि जूट इंडस्ट्री बनाउंगा, लेकिन उस रुपये से दिल्ली में मकान अपना बना लिया। यह जालसाजी है या नहीं? बैंक के आदमी उस पर एडवांस करते चले जायें तो बैंक के आफीसर जालसाज है या नहीं आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी० में? मैं तो गांव का आदमी हूँ, कम पढ़ा-लिखा हूँ। आप बताइये। जिस काम के लिए रुपया लो उस काम में खर्च न हो, यही जालसाजी है। इसकी सरकार जांच करावे और बड़े-बड़े घरानों के जरिए जो जालसाजी का काम हो रहा है उसको रोके। मैं कहता हूँ कि रिजर्व बैंक, बोर्ड आफ डाइरेक्टर टैक्सोन सब मिल कर गलमाल करते हैं। गंगोत्री से ही गन्दगी निकल रही है तो छोटी नदियों को कौन साफ करे?

SHRI JANARDHANA POOJARY; Sir, I do not want to enlarge the scope of the Calling Attention. I will confine to the reported increasing cases of forgeries in banks and a racket involving transference of black money through bank demand drafts. So, I do not want to enlarge the scope of the discussion.

The hon. Member has brought to the notice some lapses on the part of the banks. If he has got any specific instances, he can bring them to the knowledge of the Government. Definitely we will look into them. And if there are people who are involved in this type of unlawful activities, definitely we will take against those people. That I assure him.

The hon. Member has asked for the number of premises that were raided. In the main reply we have given the details. Nineteen premises have been raided on the

25th of July, 1983, and all the details have been given in the main reply in the first para itself. The hon. Member may kindly go through it. I can assure the Member that so far the Government is concerned, there will not be any deficiency on the part of the Government to look into all the allegations that have been made. On the contrary the Government is very serious to curb all these activities.

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही अब 2 बज कर 5 मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at seven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at ten minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): It is a very serious and shocking news that a large number of persons, not only in Bombay, but throughout the country, are engaged and involved in bank forgery cases and also making forged bank drafts. There are a number of instances not only in Bombay but in every part of the country. For instance, a printing press owner of Ludhiana and his close associate are involved in forged State Bank demand drafts racket. It is reported that these people are involved in forgery involving about Rs. 54 lakhs of rupees. It is stated that a person by name Mr. Ramphal, a press owner, was in Faridabad and kept a large amount of money under his name and is doing business. A sum of Rs. 1.49 lakhs was found with him. He also had with him newly purchased jewellery worth about Rs. 46,000 and a bank account operated by him under a fictitious name in the Allahabad Bank, Kisanganj Branch at New Delhi. The account was in the name of Shiva Enterprises. Ramphal also brought for himself a new car for Rs. 80,000. Another instance is that of one Mr. Surjit Singh and his close friend, who

first opened a bank account at the run-jab National Bank, Miile, Ganj Branch; then he introduced a number of other persons, a chain of accounts, where forged demand drafts were cashed and with drawn. We do not know what action the Government has taken in these cases, whether this has at all been brought to the notice of the Government. Not only in Bombay and Ludhiana but in several other places throughout the country a number of cases are taking place. I would like to know whether the Minister has got information from all over the country. If so, what are the cases which have been brought to his notice? Then, it has also been reported that there are a number of block-makers who are making blocks of forged demand drafts which are issued to different persons. This has been reported in the *Hindustan Times* of 2nd August. It has given details of some of these bank forgeries. There is also a report in the *Sunday* which my friend, Mr. Mathur, has quoted. I would like to know why no action has been taken against Mr. Raghupathy. Then, the Minister in his written statement has stated:

"The searches resulted in seizure of cash/bank drafts of Rs. 32.05 lakhs and bank accounts with balances of Rs. 18.49 lakhs were frozen. It is believed that about 100 to 150 shroffs are doing this business in Bombay and their daily turnover ranges between Rs. 50,000 to Rs. 5 lakhs."

I would like to know whether these revelations have come to him only recently or these operations were reported a long time back. If so, why has not the Government taken any action? Why have not the bank authorities taken any action all these years? Why has the Government been sleeping all these years? I would also like to know whether any Government officials, whether at the lower strata or at the higher strata, are involved in these things. These things are going on and nobody knows, neither the bank officials nor the Government. I would like to know whether bank officials are also involved in these things. If they are so involved, I would like to know

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

what action the Government has taken to curb these malpractices. I would also like to know from the honourable Minister one thing. He has stated that some vigilance commission was set up and that the Reserve Bank of India has set up some special cells for these things. What I want to know is whether these special cells and the vigilance commission appointed by the RBI would be in a position to curb these practices and whether the Government would take stern action in order to prevent all these malpractices by the banks.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, so far as the Millerganj case is concerned, already nine people have been arrested and the CBI is investigating and a sum of more than Rs. 40 lakhs has been seized. So far as this case is concerned, this is the position. Now, Sir, the honourable Member wanted to know whether there were similar cases in the past also. Para 2 of my statement clearly mentions about similar cases detected and the amount that was seized. It is clearly mentioned in para 2 of my statement So far as frauds are concerned and the question of setting up of cells by the RBI is concerned, I would say that so far it has been effective. Further, because of the checks and cross-checks, because of the constant and regular inspections by the bank authorities, by the audit departments and also by the Reserve Bank of India, we have been able to detect a number of fraud cases in the past one or two years. For example, in the year 1981, we were able to detect 1,891 cases involving Rs. 20 crores or so and, in the year 1982, we were able to detect 2,065 cases involving about Rs. 19 crores or so. So, a number of cases have been detected and the number is also increasing and we are able to detect these cases because of the checks and cross-checks and because of these inspections.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Sir, what about the blocks? What about the block-makers who make printing fake drafts?

SHRI JANARDHANA POOJARY: We have already taken action and the CBI is investigating.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ali right. Now, Mr. Nirmal Chatterjee.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, what is there to say about this? This is what I am wondering. It is because the Minister himself admits that the cases are increasing in number and he is also worried about it. Now, Sir, the first question that I would like to put is this: Why is it increasing? Is it an expression of his success in detecting more cases or is it that the cases are increasing? Why are they increasing? Is it because our economy is a socialist economy or is it because it is not a socialist economy? I was also wondering as to what we could do about it. Can he prevent, for instance, William Shakespeare from coming all the way from England and having an account opened in his name in some branch in Bombay Or Bangalore or Ludhiana? Can he do something to prevent Kalidasa from arriving here, after a thousand years, to open an account in some branch of a bank in this country? What can he do about these things? Perhaps, Sir, it is possible to do something about it For instance, it is possible to penalise these people. He says that so many cases have been detected, It will be useful for us to know, on the basis of these increased detections, how many more people, particularly those at *the top*, have been penalised. If he can take credit for the increased number of detections, let him also indicate whether more people at the top in the banking hierarchy have been also caught and penalised. I raise this question particularly because the succession of events that are taking place indicates a rather piquant situation. In the course of three months—I am quoting all these things which are certainly known to him and they know much more than what is published in the newspapers—some 75 fake DDs were presented in a particular branch of a bank. Now, if that be so, that means that the particular branch is so callous that they were unable to know about it. Either they were sleeping or

they were in collusion so that this could continue for 3 months. Now, what is the problem? The problem, first, is if you have an account, only then can you have a draft deposited there. Somebody has to introduce his name. Who introduced? William Shakespeare as one of the account holders? There must be some person. Why is he not caught? Are you prepared to ban such *benami* accounts, *benami* opening of accounts? Are you prepared to introduce a law in the banking laws that such *benami* accounts would not be permitted? That is one. Then, again, Sir, frequent references have been made to Raghupati. And in your wisdom you feel that the answer has been given. Why is he not punished? I am not satisfied. Let me ask this question. There has been an FIR against him. He has been able to accumulate Rs. 5 lakhs in the course of three years.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He says it is under investigation. It will take time.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: If there is an MR against a Government employee, is he not suspended? If it is not so, why can't Mr. Raghupati be suspended from continuing to be the Chairman and Managing Director of that bank? (*Interruptions*) Somebody comes and opens an account with Rs. 5 and on the same day he gets a loan on the basis of that Rs. 5 Rs. 7.5 lakhs. Why? For a productive purpose? In order that he may purchase a Mercedes Benz. (*Time Bell rings*). And he is not penalised. What is the answer? His answer is that there were court implications, etc. My question is, is it true that there are court implications? Is he prepared to modify the laws in such a manner that there will be no court implications? Is he prepared to do that? (*Time Bell rings*) These are not extraneous things. The culture at the top of the banks continues to be associated with monopoly houses still. Only a few years back they were owned by monopoly houses. Then you took them over. But the culture continues to be associated with

monopoly houses (*Time bell rings*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please
I conclude.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Fraud is increasing. If fraud is increasing, then can you escape the responsibility of generating an economic climate which results in that ... - (*Time bell rings*) That is my last question.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, so far as the punishing the erring people in the banks is concerned, in the year 1981, 450 people working in banks were given punishment.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: How many at the top?

SHRI JANARDHANA POOJARY: Please hear me. You have asked the question I have to reply. (*Interruptions*) In the year 1982 we have been able to punish 608 people for frauds and other such practices. Sir, the hon. Member has asked a pertinent question as to why the fraud is on the increase. As you know, Sir, before nationalisation there were about 8262 branches all over the country. Today we have 40,828 branches. More than six lakh employees are working in the banking sector. (*Interruptions*) You should not find fault with me for not answering the questions raised by my hon. friend. I am expected to answer the question and you are not. I have to satisfy him also. It is not going to help if you get excited. That is why I requested in the beginning also. Let us discuss it in a cool atmosphere. Why are frauds increasing? In every system...

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Give the figures. How many bank employees have been suspended or penalised or how many of them are at the top?

SHRI JANARDHANA POOJARY: So far as reasons are concerned, there are black-sheep in every system. In the banking system also, some unscrupulous elements are there. We have to identify them. We have to identify where the deficiency is. After that we have to take remedial measures to rectify the system. So far as Mr. Raghupati is concerned, I have already replied. I also know that the image of the institution-

[Shri Janardhana Poojary]

lion is affected by such acts. The Government is responsible. We have to see all the legal implications. We have also to find out what the ramifications are. We are equally concerned about it. I fully agree with the hon. Member that we have to take action. The C. B. I. is investigating. I will just give an example. Some gold is found in the house and there should be some explanation for it. He may say tomorrow that this gold is in his house since his marriage. At the time of the marriage, the value of the gold was Rs. 100. Now the value is Rs. 3000. Merely launching a case with the C.B.I., does not mean that the case has been proved.

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): There are two kinds of suspension, suspension after punishment and suspension pending enquiries.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: If it is proved, then he will be suspended. But there is a procedure also when the proceedings are pending.

SHRI JANARDHAN A POOJARY: We have to study all the aspects of the case. The opposition Members should not find fault with it. We have to study all the aspects. Simply because the F.I.R. has been filed, it does not mean that there is a *prima facie* case. You will agree with me.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: We are not ready to hear such a reply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhattacharya, please take your seat.

(Interruptions)

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Are you prepared to suspend him, pending investigation?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That question has been asked several times.

SHRI JANARDHAN A POOJARY: The investigation is on and the Government is very serious about it. That is why

I have said that it is under active consideration. You have made some suggestion. According to you, Mr. Raghupati should be suspended. That is your case. It is being considered. That is why I have stated that it is under active consideration. But you are not satisfied.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: If a peon is involved, if there is any cloud like this, he is first suspended.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The same point you are saying again and again.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Kindly help him to give the correct answer. He is-----

SHRI JANARDHAN A POOJARY: I also appreciated your point...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Why have you not taken the course of the normal procedure? That is the specific question. Did you advise him to go on leave because while the investigation is on, he will hamper the investigation.

SHRI JANARDHAN A POOJARY: All these aspects are being examined. You are saying that immediate action should be taken. Now, all this is being examined.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, your replies are complete, *(Interruptions)*

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: What steps are you taking to see that he does not hamper or affect the enquiry? That is the question.

SHRI JANARDHAN A POOJARY: So far as the ... *(Interruptions)* action regarding the *benami* transactions is concerned, we will look into that. You have made a suggestion and we will look into that also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rameshwar Singh.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: You ask him..

श्री उपसभापति : उनको आप शिक्षा मत दीजिए, आपसे बहुत आगे है ।
(व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभापति महोदय, जिस तरीके से बैंक अधिकारी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि सरकार इस पर अंकुश लगा पाएगी। बुनियादी तौर से मेरी मान्यता है कि जो अंकुश लगाने वाली ताकत है वह खुद ही इतनी भ्रष्ट है कि एक भ्रष्ट दूसरे भ्रष्ट पर अंकुश नहीं लगा सकता है। आप कहेंगे तो सिलसिलेवार मैं कुछ उदाहरण भी रख दूंगा। मंत्री जी से बहुत मदद के साथ हम लोग इस पर बात करना चाहते हैं। अभी यह जो सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया और उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, उन पर क्यों नहीं कार्यवाही की, इन सबको आप छोड़ दीजिए। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूँ जहां पर कि लार्ज स्केल पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यह कैसे हो रहा है इसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

उपसभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया है और हर मुख्य मंत्री को कहा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को बहुत ईमानदारी के साथ और मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। उपसभापति महोदय, मैं इसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो पूंछर क्लास को जो पैसा बैंक देते हैं मकान बनाने के लिए, कुआं खोदने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, बल खरीदने के लिए, बाज खरीदने के लिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पैसा आप अलाट करते हैं, जो पैसा सरकार देने के लिए बचनबद्ध होती है, क्या वह पैसा उस किसान को मिलता है, क्या वह बैंक देता है? आपको

इस बात की अगर जांच करानी है तो उपसभापति महोदय से पूछ लीजिए, क्योंकि ये गांव के रहने वाले हैं। हो सकता है कि ... (व्यवधान) आपको यहां न बतायें। लेकिन आप इनके कमरे में जाकर पूछिएगा। तो शायद जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ही वीटो करेंगे ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : हमको छोड़ने की कृपा करिये (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : लेकिन कमरे में जाकर के पूछिएगा ... (व्यवधान)

आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि सरकार तय करती है कि किसान पम्पिंग सेट के लिए लोन लेने के लिए एप्लीकेशन दे। प्राविजन है कि किसान के पास अगर मलिकयत है, जमीन है और सारी शर्तें वह फुलफिल करता है तो बैंक उसको रुपया देगा। एक पम्पिंग सेट के लिये बाजार में दाम 3800 से 4200 रुपये तक देना पड़ता है लेकिन उसको बैंक 7000 में या 6500 में दिलवाता है। किसान चाहता है कि उस मशीन को वह न खरीदे। वह तो चाहता है कि 3800 या 4200 वाली मशीन वह खरीदे लेकिन आप ने कंडीशन लगा दी है कि बैंक की अयारिटीज और उस के मुलाजिम जो दिलवायेंगे वही मशीन जो वे रिकमेंड करेंगे वही उस को लेना पड़ेगी और बैंक उस को चेक न देकर उस का पैसा उस कंपनी को ही देगा जिस की मशीन होगी। इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी ज्यादाती संसार में आप को सुनने को नहीं मिलेगी। हम अगर नकद पैसा लेकर जायें तो वह मशीन हम 3800 में खरीद लाते हैं, मगर सरकारी बैंक, बी० डी० ए० और गांव में जिस को आप लेखपा ल

[श्री रामेश्वर सिंह]

कहते हैं वह सब मिल कर उस किसान को मजबूर करते हैं कि वह मशीन वह 3800 में खरीदे और उस को वह खरीदनी पड़ती है और इसके लिये किसान को दोड़ते दोड़ते हैरान हो जाना पड़ता है और उस का आधा पैसा ये लोग खा जाते हैं।

श्री उपसभापति : इस को छोड़िये । अब दूसरा प्वाइंट लीजिए और आगे चलिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : और आधा रुपया मशीन के लिये चला जाता है। खैर, अब मैं आगे चलता हूँ। उद्योग के मामले को लीजिए। अभी मैं पढ़ रहा था प्रोसीडिंग्स जाली नोटों के बारे में। सरकार को पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने जाली नोट चल रहे हैं। शायद यह प्वाइंट छूट गया है। हांगकांग और चीन से ...

श्री उपसभापति : आप के 6 मिनट हो रहे हैं और यह विषय है नहीं।

श्री रामेश्वर सिंह : तो बाहर से नोट छप कर आते हैं और हर बैंक के नहीं तो कम से कम हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे बैंक हैं जिन के अफसर और मैनेजर वगैरह उन से मिले रहते हैं और 50 परसेंट पर उन का सौदा तय हो जाता है। और जब वह लोगों को बैंक से रुपया देते हैं तो 5 गड्डी असली नोटों की दे देते हैं और उस में 2 गड्डी जाली नोटों की दे दी जाती है। तो आप का ध्यान इस तरफ भी जाना चाहिए।

श्री उपसभापति : आप के सात मिनट हो गये हैं।

श्री रामेश्वर सिंह : तो आप हम को दो मिनट और दे दीजिए। एक है सहकार प्रकाशन संस्थान, लखनऊ। यह सहकारी संस्था बन कर रजिस्टर्ड हो गयी और नियम के मुताबिक इसका जितना रुपया जमा होना चाहिए था रजिस्ट्रेशन के लिये 12 या 14 हजार, वह भी जमा हो गया और उसके बाद बैंक उस को कितना लोन देता है। मैं इस को सुना देता हूँ। मैं नाम सुना देता हूँ।

श्री उपसभापति : नहीं। नाम नहीं।

श्री रामेश्वर सिंह : तो उन का पता कैसे चलेगा।

श्री उपसभापति : देखिये। रामेश्वर सिंह जी, आप अनावश्यक बात मत कहिये। वह रुपया देते हैं, किस को देते हैं उस सब बतलाने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न है आप उसी पर रहिये। यह बैंक के डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के बारे में है लेकिन आप कहां से कहां चले गये। बैं में तो वैसे हजारों चीजें हैं।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं काम की बात पर आता हूँ। किसी विरोध वाले का नाम इस में नहीं है।

श्री उपसभापति : आप कृपया कर सवाल पूछिये।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं सवाल पूछता हूँ। क्या आप जांच करायेंगे। 20 हजार रुपया * को दिया गया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: N» names will be recorded. I will not allow it. He cannot reply to these points. This is completely irrelevant.

*Not recorded.

PROF. SOURENDRA BHATTACHAR-JEE: The Member will take the responsibility.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is completely irrelevant.

श्री रामेश्वर सिंह : क्यों आप नहीं एलाऊ करेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जो बात अनपार्लियामेंटरी है उसको तो आप मत रेकार्ड कराइये, लेकिन . . .

श्री उपसभापति : जिस का कोई आघार नहीं है, अनावश्यक है, वहीं बात वे कह रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जो बात वे कह रहे हैं, सही है। भले ही वह विषय के बाहर हो।

श्री उपसभापति : आप सवाल करिये, इसको छोड़िये। जब बैंक के संबंध में कोई बिल आये तो उस समय इस तरह की बहस करियेगा और वह उस का जवाब दे गे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : आप यह क्या कर रहे हैं ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I will not allow it. This is completely irrelevant.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : लेकिन आप यह पहली बार कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : यह बिल होता तो वे सब बातें कह सकते थे लेकिन यह कालिग प्रॉटेशन है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप

अपने अधिकार का उपयोग करें, बिलकुल ठीक है, लेकिन सदस्यों को जो बात कहने का अधिकार है वह उन को उपयोग करने दीजिए और उन को अपनी बात कहने दीजिए। आप उन को टोक दीजिए कि वे विषय के बाहर न जायं लेकिन यह रेकार्ड में नहीं जायगा यह कहना ठीक नहीं होगा।

श्री उपसभापति : आप ने मिनिस्टर को बताया नहीं और यहां चार्ज लग रहे हैं।

PROF. SOURENDRA BHATTACHAR-IEE: It is a question of forgery. Why can't he cite such cases? Do you mean to lay that only generalities will be die-cussed in the Calling Attention? How can you say that?
{Interruptions}

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: How can you say that what he is laying will not go on record? You can say that you will not allow him to speak further. You can ask him to sit down. But you cannot stop him going on record unless what he says is unparliamentary. {Interruptions}

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not allow irrelevant things.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: You can ask him to stop. You can say that he is going out of the way. But you cannot say that what he is saying will not go on record.
{Interruptions}

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This can not go on record. I will not allow these things. I will not allow irrelevant things

SHRI RAMESHWAR SINGH;*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rameshwar Singh, please sit down. It

*Not recorded.

[Mr. Deputy Chairman] to hon. Minister reply. If you do not want to put any questions, please sit down.

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You do not name anybody. I will not allow.

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not to be recorded. This will not go on record.
(Interruptions')

SHRI HAREKRUSHNA MAJICK (Orissa); Sir, I would like to know under which rule you are saying that this will not go on record. Is it unparliamentary?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not allow irrelevant things, fantastic allegations and baseless charges.

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will not allow. This will not go on record.

SHRI RAMESHWAR SINGH:*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. You are wasting the time of the House.

मिर्जा इरशाद बेग अबूबक़र (गुजरात) :
उपसभापति जी, मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है। प्वाइंट आफ़ आर्डर यह है कि जब प्रापकी ओर से क्लिग मिल जाती है तो उसके बावजूद भी इस सदन का समय इस तरह से कोई सदस्य व्यतीत करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान है या नहीं? प्रगर आपके क्लिग के बाद भी माननीय सदस्य बोलना जारी रखेंगे तो कार्यवाही कैसे चलेगी?

श्री उपसभापति : मैंने एक क्लिग दी फिर भी आप सदन का समय ख़बाद करना चाहते हैं तो मुझे मज़बूरन सदन को स्थगित करना पड़ेगा। मैंने

*Not recorded.

क्लिग दे दी, मैंने कह दिया कि जो आप फ़िजूल की बातें कह रहे हैं वह रेकार्ड में नहीं जाएगा। आप सवाल पूछते नहीं हैं आरोप लगाते हैं।... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : मैं सवाल पूछ रहा हूँ। क्या साहित्यकार प्रकाशन सहकारी समिति की आप जांच करायेंगे कि 5 लाख रुपया बैंक से फोरजरी करके, गलत दस्तखत करके जो निकाला गया उसकी जांच करायेंगे?.. (व्यवधान)

श्री उपसभापति : हो गया। कई बार आपने बोल दिया। सदन में बहरे लोग नहीं बैठे हैं।... (व्यवधान)

SHRI IANARDHANA POOJARY: If there are any malpractices anywhere, Government will not shirk its responsibility and we are keen to curb such activities. Now, the hon. Member can write to us giving the details and we will look into it. Then, so far as ----- (Interruptions)

श्री रामेश्वर सिंह : इसका जवाब तो दिया ही नहीं।... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : रामेश्वर सिंह जी, आप क्या समझते हैं कि मंत्री और सदन बहारा है। आप बैठ जाईए। रत्ती भर माननीय सदस्य की कोई परम्परा नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि आप लिखकर भेज दीजिए, फिर भी आप बोल रहे हैं। इसलिए कि सदन का प्रोटेशन लेकर आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप लिखकर क्यों नहीं भेज देते?

श्री रामेश्वर सिंह : आप कैसे समझ रहे हैं कि गलत हैं?... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : लिखकर क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कह दिया है तो बात खत्म हो गई।... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह *

श्री उपसभापति : यह सदन आपका नहीं है कि कुछ काम ही न हो। . .
(अवधान)

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, so far as the implementation of the I.R.D. programme is concerned, the hon. Member has brought to the notice of the Government some of the deficiencies and, in fact, in order to look into these complaints and also to have a regular flow to the poorer sections under this programme, as I said in the forenoon, our Finance Minister has written to the Chief Ministers to set up advisory committees. The committees will have three non-officials. There will be one MLA, one branch manager of the lead bank there and also the BDO and also the Panchayat member. These people will look into all these aspects and they will see that the programme is implemented effectively. In addition to that, in the consultative committee there will be one subgroup and the Finance Minister has written to all the State Governments, particularly the Chief Ministers, to set up grievance cells under that. In that cell also there will be non-officials. They will go into all corrupt and malpractices, which will be looked into by the Government: and also by the Reserve Bank of India.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister has said that this subject ought to be discussed in a cool and restrained atmosphere. I respectfully agree with him. From the discussions already held and the replies given by the hon. Minister including his written reply, it is clear that, since independence there has been a phenomenal development in banking services in our country. On the one hand, there has been increase in the volume of work, on the other hand, deterioration of the quality of service. Hon. Members have referred to complaints by customers, large-scale frauds, defalcation of funds, corruption, bribery etc. It is also more or less clear from the statements made by the hon. Minister

*Not recorded.

that things are coming to such a pass that the general depositors are losing their confidence in the banking system as such, including the Reserve Bank of India. Sir, if the hon. Minister wants he can nominate a representative, I can take the representative to the branches of several well-known banks in South Calcutta, Central Calcutta and North Calcutta. I will show to his accredited representative that no employee, no officer, not even the manager turns up before quarter to eleven or sometimes eleven o'clock. I have personally spoken to managers of important banks, branch managers, as to why they could not control their employees, why they could not control their officers. They said, "Sir, I am absolutely helpless, I have no control over them. If

I ask them to do any work, if I take them to task for making any default, I shall be immediately gheraoed, my life would be in danger." We give our savings bank books to be written up by the banks for debit and credit entries, for entry of interest and for entry of fixed deposit interests. The pass books are returned to us after a fortnight or so without any entry. This is the state of affairs going on in different banks in all parts of the country. All that we see is proliferation of branches. I am glad that the hon. Minister in his statement has referred to a meeting on the 14th April, 1983, of chief executives of public sector banks which was addressed by the hon. Finance Minister on different aspects of these problems. It is said here at page 2 of his statement that these executives have been advised to review and revamp the vigilance machinery. Sir, I want specifically to ask the hon. Minister as to the composition and structure of this vigilance machinery. What kind of vigilance machinery is it going to be? Is every bank going to have a Vigilance Cell of its own at its headquarters which will continuously go on touring all the branches of these banks in a particular area, so that proper functioning is ensured? Would this Vigilance Cell consist, amongst others, of efficient, experienced police officers who have been trained in dealing with crimes of this nature? And would such cells be headed by persons of the rank of IGP or DIGP? I know you have your difficulties. You may not be getting serving police offi-

[Shri Sankar Prasad Mitra]

case for this kind of work. But if you are not getting serving police officers to man these Vigilance Cells, you have to recruit experienced police officers from superannuated officers, from officers who have retired. Unless you strengthen your Vigilance Cells and unless these Vigilance Cells really operate in all seriousness, this type of mischief that is going on can never be stopped. I can tell you, not as a Member of Parliament but as an ordinary member of the public must sooner or later we shall lose all faith in the banking system that you are administering.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I am very grateful to my hon'ble friend and in fact after taking over the charge of this Ministry, I went through the debates of hon. Members from both sides of the House—the Treasury benches and also from the Opposition benches—and I have gone through the paper clippings and editorials appearing in the papers. In order to verify things, I paid surprise visits, incognito visits to some of the branches through out the country and whatever my hon. friend has stated, I fully endorse his views. I have seen personally when I was there in some of the banks for about 40-45 minutes, incognito and I found that these are the deficiencies. In fact, our hon. Finance Minister, after my reporting to him, called a meeting of the Chief Executives of the banks and emphasised the need for improvement. He also has given clear instructions to all the Chief Executives and in pursuance of these instructions, they have started paying surprise visits to all the branches. Not only that, in the banking system so far as punctuality is concerned, the checking in the morning...

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: Mr. Minister, I forgot to tell you that they come at 11 o'clock and then the first half an hour is spent in gossip. The customer has to wait. I do not know whether you have observed that.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I have also seen. In one of the branches, out of 106 employees, only two employees were in their seats. I have recorded the

statements also. For your information, Sir, and through the House I can tell the hon. Members that this was going on. That is why effective measures have been taken. For the information of the hon. Members, I can tell you that there is some visible improvement and last year only we have saved the wastage in the

form of overtime. Last year only 3 P.M. we saved wastages in the form of overtime, to the tune of Rs. 16,86,00,000, for the country. Now, so far as the implementation of the programme also is concerned, and the efficiency in banks is concerned, I fully agree that in some of the branches there is a deterioration in service, the quality of service has gone down. That is why the Government has taken a very serious view of it and so many remedial measures have been taken. Sir, in this context, I would also say that where-ever there are such instances, they should be brought to the notice of the Government. In Delhi when Parliament is in session, from 16th of August, the bank people will be observing a week for inculcating efficiency, and the executives will be going to branches and will see. We are making a beginning in Delhi. All the chief executives, the executive officers, will be going to branches and will see the quality of service. If there are any complaints, on the spot, decisions will be taken. All these steps are being taken. I am very happy that the hon. Member has come out clearly with these deficiencies before the House.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1983-84

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI); Sir, I beg to lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1983-84.

REFERENCE TO THE NEED FOR IMMEDIATE REGISTRATION OF RAPE CASES BY POLICE

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) :
श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से